सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-6 • 27 JUNE TO 03 JULY 2025 • VOLUME 48 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

मेहनत एक सुनहरी चाबी है।
जो बन्द भाग्य के भी दरवाजे
खोल देती है।

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	33°	26°
शनिवार	35°	29°
रविवार	35°	28°
सोमवार	35°	29°
मंगलवार	35°	29°
बुधवार	35°	29°
वीरवार	35°	29°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

एससीओ को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए : राजनाथ सिंह

कहा- आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून, 2025 को चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति में बदलाव की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की तथा सदस्य देशों से सामूहिक सुरक्षा और रक्षा हेतु इस खतरे को निर्मूल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रक्षा मंत्रियों, एससीओ महासचिव, एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे (आरएटीएस) के निदेशक और अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं तथा बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद इन समस्याओं का मूल कारण हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति और समृद्धि, आतंकवाद और गैर-राजकीय तत्वों या आतंकी समूहों के पास सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के साथ सह-अस्तित्व नहीं रख सकती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने संकीर्ण व स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के जवाब में आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का तरीका भारत में एलईटी के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य-सहिष्णुता उसके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के दोषियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता दोहराई।

उन्होंने आतंकवाद के हर कृत्य को आपराधिक और अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की भारत की प्रतिवद्धता भी व्यक्त की। रक्षा मंत्री ने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया और इस चुनौती से निपटने में आरएटीएस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान जारी किए गए 'आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला' पर एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का संयुक्त वक्तव्य हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन सहित आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का मुकाबला करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला

औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी

औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति देने के उद्देश्य से उठाया गया कदम

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत मदों के लिए उपयोग की अनुमति देने वाली पंजाब की हस्तांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि, औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा। **लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों/शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की मंजूरी :** कैबिनेट ने विशेष रूप से पी.एस.आई.ई.सी. के प्रबंधन वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दे दी। ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें परिवर्तन संबंधी जटिल धाराएँ शामिल थीं, जिसके कारण संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां आ रही थी।

एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल नियम-2021 में संशोधन : कैबिनेट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल नियम-2021 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। वर्तमान में जिला स्तर पर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में काम कर रही हैं। हालांकि, इस एक्ट के तहत अवार्ड्स से संबंधित भुगतानों में देरी हो रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर अब एक ऐसा ढांचा बनाया जाएगा, जिससे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1887 के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे अवार्ड्स की वसूली जल्द हो सके।

पंजाब जल संसाधन विभाग जूनियर इंजीनियर्स (ग्रुप-बी) सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी : कैबिनेट ने पंजाब जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर्स (ग्रुप-बी) से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत जे.ई. की 15 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत रिक्तियां जूनियर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयरों, वर्क मिस्त्रियों, अर्थ वर्क मिस्त्रियों और अन्य से भरी जाएंगी।

वित्त विभाग के तहत विभिन्न निदेशालयों के विलय को हरी झंडी : प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए कैबिनेट ने वित्त विभाग के तहत आने वाले विभिन्न निदेशालयों के विलय को मंजूरी दे दी। इसके तहत छोटी बचत, बैंकिंग और वित्त, और लॉटरी निदेशालयों का विलय होगा और अब इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ स्मॉल सेविंग्स, बैंकिंग और लॉटरी होगा। डीपीईएड और डीएफआरईआई का भी आपस में विलय होगा और इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा। ट्रेजरी और अकाउंट्स, पेंशन और एन.पी.एस. के विभिन्न निदेशालयों का भी आपस में विलय होगा और अब इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, पेंशन और एनपीएस होगा। इस पुनर्गठन से राज्य को लगभग 2.64 करोड़ रुपए वार्षिक बचत होने की संभावना है।

स्टेट एसएनए ट्रेजरी के लिए नई रिक्तियों के सृजन को मंजूरी : कैबिनेट ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार चंडीगढ़ में स्थापित स्टेट एस.एन.ए. ट्रेजरी के लिए नई रिक्तियों के सृजन को भी सहमति दे दी। केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत फंडों का हस्तांतरण अब एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के माध्यम से होगा। स्टेट एस.एन.ए. ट्रेजरी को कार्यशील करने के लिए नौ रिक्तियों को मंजूरी दी।

डीआरआई ने 'ऑपरेशन डीप मेनिफेस्ट' के तहत जब्त किए 39 कंटेनर, एक गिरफ्तार

नई दिल्ली (जालंधर ब्रीज). एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अन्य देशों, मुख्य रूप से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से पाकिस्तान में तैयार की गई सामग्रियों के अवैध आयात को लक्षित करते हुए "ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट" नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य के 1,115 मीट्रिक टन माल ले जाने वाले 39 कंटेनर जब्त किए गए हैं, जो आयात नीति की शर्तों और पाकिस्तान में तैयार की गई सामग्रियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन है। आयात करने वाली एक फर्म के एक भागीदार को 26.06.2025 को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद, सरकार ने 2 मई, 2025 से पाकिस्तान से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया था। पहले, ऐसे माल पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता था। इन कड़े उपायों के बावजूद, कुछ आयातक माल की उत्पत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर और संबंधित शिपिंग दस्तावेजों में हेराफेरी करके सरकारी नीति को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा इतिहास

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा शुभांशु का यान, देशवासियों को किया नमस्कार

नई दिल्ली. फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के 28 घंटे बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए क्योंकि गुरुवार को ऐग्ज़ियम-4 (एएक्स-4) मिशन सफलतापूर्वक ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला से जुड़ गया। यह मील का पत्थर भारत के लिए मानव अंतरिक्ष यान में विजयी वापसी का प्रतीक है, जो 1984 में राकेश शर्मा के अग्रणी मिशन के 41 साल बाद आया है। जैसे ही शुभांशु शुक्ला ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखा, उनके गौरवान्वित परिवार ने पृथ्वी से इस महत्वपूर्ण क्षण को देखा। मिशन पायलट के रूप में सेवारत शुक्ला के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिशन कमांडर पैगी व्हिटसन और पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ सावोज़ उज़्नान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस मिशन के साथ ही पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी पहली बार आईएसएस पहुंचे हैं।

ट्रंप नहीं सुधरे तो बड़ी कीमत चुकाएंगे युद्धविराम के बाद पहली बार बोले खामेनेई

तेहरान. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने युद्धविराम के बाद अपने पहले संबोधन में कहा है कि उनके देश ने 'अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है'। खामेनेई ने साथ ही कहा कि यदि अमेरिका भविष्य में कोई हमला करता है तो ईरान मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके जवाब देगा। 86 वर्षीय खामेनेई ने कहा कि ईरान पर किया गया कोई भी हमला "बहुत भारी कीमत" लेकर आएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे (क़तर में स्थित) पर हमला किया था, जब वॉशिंगटन ने इज़राइली हमलों में भाग लिया था। ईरान और इज़राइल के बीच युद्धविराम के बाद टेलीविज़न पर देश को पहली बार संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ने अमेरिका को तमाचा मारा। हमने क्षेत्र में अमेरिका के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला किया। बताया जा रहा है कि खामेनेई का रिकॉर्डेड बयान सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। पिछली बार की तरह वह इस बार भी एक अज्ञात स्थान से बोल रहे थे, जहां उनके पीछे एक भूरे रंग का पर्दा, एक ईरानी झंडा और उनके पूर्ववर्ती रूहोल्लाह खोमैनी की तस्वीर थी।

एआई-171 ब्लैक बॉक्स की मेमोरी हुई एक्सेस, डेटा निकालने का प्रोसेस शुरू

अहमदाबाद (जालंधर ब्रीज). एअर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को अहमदाबाद में टेक-ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। इस हादसे की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) को बड़ी सफलता मिली है।

सरकार ने गुरुवार को बताया कि विमान के ब्लैक बॉक्स से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनका डेटा डाउनलोड कर लिया गया है और अब इनका विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के अनुक्रम को फिर से बनाना और विमानन सुरक्षा को बढ़ाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना है। सभी कार्यवाहियां घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में समयबद्ध तरीके से की गई हैं। आईसीएओ शिकागो कन्वेंशन (1944) के हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में भारत आईसीएओ अनुलग्नक 13 और विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के अनुसार विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ऐसी जांच के लिए नामित प्राधिकारी है।

सात मुख्य कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों (सी.ए.ओ.) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए हैं। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में पीछे रहने वाले जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश देने के एक दिन बाद की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा नियमों के अनुसार आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार की कर्तव्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।

अब नशे के कारोबार में शामिल 'जरनैलों' की बारी : मुख्यमंत्री

मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई ने नशे से संबंधित राजनीतिक दलों के गंदे गठजोड़ को उजागर किया

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि छोटे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब इस कारोबार में शामिल बड़े तस्करों की बारी है और उन्हें इस कारोबार में अपनी संलिप्तता के परिणाम भुगतने होंगे। अपने आधिकारिक आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने नशे और इस काले कारोबार में शामिल या संरक्षण देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि छोटे तस्कर केवल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं, जबकि पूरा नेटवर्क चलाने वाले बड़े तस्कर लंबे समय से जवाबदेही से बचते रहे हैं। अब इन बड़े तस्करों की बारी है। भगवंत सिंह मान ने दृढ़ता से कहा, "इस धंधे में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही छोटे-छोटे इलाकों में काम करने वाले तस्करों को जेलों में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस घिनौने कारोबार में शामिल सभी तस्करों को जेल में डालने की गारंटी दी थी। अब यह वादा पूरा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा कार्रवाई ने नशे के काले धंधे की कमर तोड़ दी है।

भगवंत सिंह मान ने खुलासा किया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें हवाला कारोबार का रिकॉर्ड शामिल है, और यह इन कारोबारियों के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने वादा किया कि यह नजीर बनने वाली कार्रवाई दूसरों को भी इस धंधे में आने से रोकेगी। उन्होंने सभी दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे 'युद्ध नशे के विरुद्ध' की सफलता के बारे में बताया और कहा कि कई तस्कर पंजाब छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब व्यापक जन समर्थन के साथ जन आंदोलन बन गया है। मुख्यमंत्री ने नशे की बुराई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए गांवों की पंचायतों की सराहना करते हुए इसे पंजाब में नशे के खतरे को खत्म करने के लिए रचनात्मक कदम बताया। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा मजीठिया के पक्ष में बयान देने से नशा तस्करों को संरक्षण देने वाला राजनीतिक गठजोड़ उजागर हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी ने नशे के मुद्दे पर पारंपरिक राजनीतिक दलों के गंदे गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इनकी गतिविधियों ने पंजाब को तबाह कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कारोबार में शामिल अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी या ढहाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में आए पैसे की पूरी श्रृंखला से संबंधित हर कड़ी की गहन जांच होगी। जिन्होंने इस काले कारोबार से बड़ी-बड़ी संपत्तियां बनाई हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा।

बिक्रम मजीठिया को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा

चंडीगढ़. शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली जिला अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजिलेंस ब्यूरो ने अदालत में पेश किया। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद से ही अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए अदालत परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजीठिया को 7 दिन की पुलिस हिरासत पर पंजाब आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि अदालत ने भी माना है कि आगे की जांच की जरूरत है। पंजाब सरकार और विजिलेंस विभाग ने पूरे तथ्यों के साथ मामले को अदालत में उठाया। नशे की वजह से अपने बच्चों को खोने वालों को न्याय मिले। पंजाब में नशा फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

केरल जाने का है प्लान तो IRCTC के इस टूर पैकेज को कर लें बुक

Trevelling बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से केरल के इस टूर प्लान को बुक कर सकते हैं। जहां आप केरल के इस रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से टूर स्टार्ट कर सकते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

बारिश का मौसम जून से लेकर पूरा सितंबर तक चलता है। इस बीच अगर आपका भी घूमने का प्लान है तो केरल बेस्ट प्लेस है। जहां के सुंदर नजारे मानसून में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर केरल घूमने के लिए जून, जुलाई,अगस्त और सितंबर चारों महीने के लिए प्लान है। जिसकी बुकिंग करा कर आप आराम से केरल के इन चार प्लेसेज की सुंदरता को निहार सकते हैं।

कितने दिन का है ये ट्रिप प्लान

आईआरसीटीसी का ये ट्रिप प्लान पूरे 3 रात और 4 दिन का है। जिसमे आप केरल की 4 जगहों की सैर कर सकते हैं। जून से लेकर अगस्त तक ये ट्रिप 1 से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक है। वहीं सितंबर महीने में केवल 1 तारीख से 23 तारीख तक ही इस टूर की बुकिंग होगी।

कितना है किराया

आईआरसीटीसी के इस टूर प्लान का किराया जून के महीने में प्रति व्यक्ति 35,725 रुपये है। वहीं दो लोगों के लिए 18,390 रुपये देने होंगे और तीन लोगों के लिए ये किराया 14,205 रुपये हो जाएगा। जबकि बच्चे के लिए अलग बेड की बुकिंग 6,145 रुपये में होगी। वहीं जुलाई से लेकर सितंबर के लिए अलग कीमत तय की गई है। जिसकी जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है।

किन जगहों की कराएगा सैर

केरल के चार टूरिस्ट प्लेस को 3 रात और 4 दिन के टूर प्लान में जोड़ा गया है। इनमे मन्नार, थेक्कड़ी, कुमाराकॉम और अलेप्पी शामिल हैं। ये चारों की जगहें अपने खूबसूरत हरे-भरे पहाड़ों और सुंदर नजारों के लिए फेमस हैं। रेलवे की तरफ से दी जारी सुविधाओं की मदद से केरल के इस ट्रिप प्लान को आसान और सुविधाजनकर बनाया जा सकता है। तो अगर आप भी बारिश में कीं घूमने का प्लान बना रहे तो केरल की हरी-भरी वादियों को आराम से देख लें।

मिलेगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी की इस टूर प्लान बुकिंग में होटल के साथ कैब की सुविधा और मील भी ऐड है। वहीं ये टूर प्लान पूरी तरह से इंस्श्योर्ड है। जिससे फैमिली की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

FASHION

जींस या ट्राउजर सारे बॉटम के साथ स्टाइलिश दिखेंगी ये शॉर्ट कुर्ती, देख लें डिजाइन

गर्मियों के साथ बारिश के मौसम में अगर कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक की तलाश में हैं तो कॉटन फैब्रिक पर ये 7 तरह की ब्यूटीफुल शॉर्ट कुर्ती सिलवा लें। ये जींस से लेकर पैंट हर बॉटम के साथ फिट बैठेगी।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

शार्ट कुर्ती डिजाइन

गर्मी हो या बरसात दोनों ही मौसम में कंफर्टेबल कपड़े पहनने का मन करता है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर कामकाजी महिला हैं तो शार्ट कुर्ती की इन डिजाइन को सिलवाकर रख लें। ये कुर्ती की डिजाइन जींस, पैंट और ट्राउजर जैसे कई तरह के बॉटम के साथ फिट बैठती है और स्टाइलिश दिखती हैं।

रैप डिजाइन कुर्ती

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन काफी स्टाइलिश है और कैजुअल के साथ फॉर्मल में भी खूबसूरत दिखेगी। जींस के साथ ही पैंट के साथ भी इसे पेयर किया जा सकता है।

कॉलर वाली ए लाइन शार्ट कुर्ती

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन बेहद क्यूट है। मेपल कॉलर के साथ रैप स्टाइल और साथ में ए लाइन डिजाइन इसे डिजाइनर और फैशनेबल बना रही है।

शर्ट स्टाइल कुर्ती

शार्ट कुर्ती फॉर्मल लुक के लिए सिलवानी है तो शर्ट स्टाइल की सिलवा लें। मेंडरिन कॉलर इसे फेमिनिन लुक देगा और ट्राउजर के साथ परफेक्ट दिखेगी।

शर्ट डिजाइन प्लीटेड कुर्ती

शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन भी काफी फैशनेबल है। कमर के पास प्लीट्स पड़ी होने की वजह से ये मोटी महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही जींस और पैंट दोनों के साथ स्टाइलिश दिखेगी।

बटन डाउन कुर्ती

बड़े-बड़े बटन और जैकेट वाले कॉलर के साथ इस तरह की शार्ट कुर्ती को

स्टिच करवाएं। ये स्टाइलिश लुक देगी और गर्मियों में आराम भी।

हाई नेक कुर्ती

गर्मियों में कॉटन फैब्रिक की स्लीवलेस कुर्ती में इस तरह जीरो हाई नेकलाइन बनवाएं। ये ऑफिस वियर में ब्यूटीफुल दिखेगी।

स्लीवलेस ए लाइन कुर्ती

कॉलेज गोइंग गर्ल इस तरह की ए लाइन स्लीवलेस कुर्तियों को सिलवाएं। जो बारिश के मौसम में कैप्री के साथ स्टाइलिश दिखेंगी और आराम देंगी।

दिल की सेहत का ख्याल रखेंगी ये 5 जीरो ऑयल रेसिपीज, नसों में जमा गंदगी होगी साफ

अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और अपने कोलेस्टॉल लेवल को कंट्रोल रखने के लिए जीरो ऑयल रेसिपी बनाकर खाना चाहते हैं तो टाई करें ये रेसिपीज। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ आपकी दिल की सेहत का भी खास ख्याल रखेंगी।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

लाइफस्टाइल की बिगड़ती आदतें और खानपान की अनदेखी, आजकल कम उम्र में ही लोगों को दिल का मरीज बना रही है। इतना ही नहीं ज्यादा तला-भूना खाने से व्यक्ति को बदहजमी, एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी समय रहते अपने दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ये जीरो ऑयल रेसिपी शामिल कर सकते हैं। यह सभी रेसिपी ना सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि काफी हेल्दी भी हैं। इनके नियमित सेवन से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। तो अगर आप भी नाश्ते से लेकर डिनर तक के लिए, खाने के हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये जीरो ऑयल रेसिपी आपके काम आ सकती हैं।

जीरो ऑयल रेसिपी के बेस्ट ऑप्शन

स्टफ्ड इडली - बच्चे हों या बड़े, नाश्ते से लेकर लाइट डिनर की चाह रखने वाले लोगों को स्टफ्ड इडली का ऑप्शन बहुत पसंद आता है। यह एक हेल्दी डिश है, जिसे आप बेहद आसानी से बिना तेल के अपने घर में बना सकते हैं। यह खाने में टेस्टी और सेहत के लिए हेल्दी होती है। स्टफ्ड इडली को आप सूजी, दही और कई तरह की सब्जियों की मदद से बनाकर तैयार कर सकती हैं।

ऑयल फ्री पोहा - भारत में नाश्ते में पोहा खाने वाले लोगों की गिनती कम नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इसे एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। पोहा पूरा दिन पेट भरा रखने के साथ वेट लॉस में भी मदद करता है। पोहा को ऑयल फ्री बनाने के लिए आप इसे कड़ाही की जगह माइक्रोवेव में बनाएं।

पास्ता सलाद - बच्चों का फेवरेट पास्ता दिल की सेहत के लिए भी अच्छा फूड ऑप्शन हो सकता है। इस जीरो ऑयल रेसिपी को बनाने के लिए गर्म पानी में पास्ता डालकर उबाल लें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, काली मिर्च और नमक मिला लें। आप चाहे तो स्वाद बढ़ाने के लिए पुदीने की चटनी का भी यूज कर सकते हैं।

अंकुरित मूंग दाल चाट - मूंग दाल चाट, स्वाद और

सेहत दोनों के लिए बेस्ट मानी जाती है। इस चाट को ऑयल फ्री बनाने के लिए उबली हुई अंकुरित मूंग दाल में प्याज, टमाटर, नींबू का रस, नमक और चाट मसाला मिलाकर खाएं।

वेजिटेबल सूप - कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखकर दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए आप कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो बीन्स और दाल वाला वेजिटेबल सूप भी ट्राई किया जा सकता है। बीन्स और दाल से बना सूप, वेट लॉस के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद कर सकता है। जिससे व्यक्ति को लिए दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बता दें, यह सूप फाइबर और पोटेशियम का भी अच्छा स्त्रोत है।

बच्चों को डिसिप्लिन करते समय पेरेंट्स अकसर करते हैं ये गलतियां

जालंधर ब्रीज (फीचर) . अनुशासित जीवन व्यक्ति के लिए सफलता की राह को आसान बना देता है। यही वजह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ही डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि कई बार ऐसा करते हुए उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जो ना सिर्फ बच्चों के मन में अपने अभिभावकों के लिए मन में क्रोध और द्वेष का भाव उत्पन्न करती हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बच्चों को माता-पिता से दूर कर देती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बच्चों को अनुशासित करना सही बात है, लेकिन ऐसा करते हुए पेरेंट्स अक्सर कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चे को खुद उनसे दूर कर देती है।

बच्चों के प्रति नेगेटिव रवैया : अकसर देखा जाता है कि माता-पिता बच्चे को सही चीज सिखाने के लिए भी कई बार नेगेटिव तरीका और बातें अपनाने लगते हैं। जिससे खुद बच्चों का मन बहुत नेगेटिव हो जाता है और वह माता-पिता के उस रवैया को लंबे समय तक अपने दिमाग में बनाए रखते हैं।

पेरेंट्स का खुद अनुशासनहीन होना : कई बार पेरेंट्स बच्चों को तो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं लेकिन खुद उन्हीं के सामने अनुशासनहीन व्यवहार करने लगते हैं। याद रखें बच्चा जैसा आपको करते हुए देखेगा वैसा ही खुद भी करने लगेगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ पेरेंट्स को यह सलाह देते हैं कि बच्चे के सामने ऐसी कोई चीज न करें, जो उसके दिमाग पर बुरा असर डाले।

सख्त नियम : पेरेंट्स कई बार अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए बेहद सख्त नियम बना देते हैं। जिनका पालन करना किशोर बच्चों के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह गलती करने से बचें। बच्चों के लिए सख्त नियम बनाने की जगह उन्हें समय की अहमियत समझाएं।

फैटी लिवर को रिवर्स करना है तो खाएं ये स्नैक्स - हार्वर्ड के डॉक्टर

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

फैटी लिवर की समस्या दिन पर दिन कॉमन होती जा रही। जिसके लिए आमतौर पर सिडेंटरी लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड डाइट जिम्मेदार है। बिना एल्कोहल पिए ही ज्यादातर लोग फैटी लिवर से ग्रस्त हैं। लेकिन इस समस्या को खानपान की मदद से ठीक किया जा सकता है। हार्वर्ड से ट्रेंड लिवर और गट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने स्नैक्स कॉम्बिनेशन को शेयर किया है जो फैटी लिवर को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि इन स्नैक्स को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ खाया जाए। ये 4 स्नैक्स लिवर फैट मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन और गट हेल्थ पर असर डालते हैं।

खजूर और अखरोट

खजूर को काफी सारे लोग बहुत ज्यादा मीठा समझकर खाना इग्नोर करते हैं। लेकिन खजूर में सॉल्यूएबल फाइबर होता है जो शुगर के अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को कम कर लिवर में फैट जमा होने के प्रोसेस को कम करता है। अगर खजूर को अखरोट के साथ मिलाकर खाया जाए तो कॉम्बिनेशन फैटी लिवर के लिए फायदेमंद है।

रॉ हनी विद एप्पल एंड सिनेमन

हेल्दी और स्वीट स्नैक्स रॉ हनी विद एप्पल एंड सिनेमन काफी यम्मी लगता है। सेब में पेक्टिन होता है जो गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है वहीं रॉ हनी की थोड़ी मात्रा लिवर मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी होती है। इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन सप्ताह में एक से दो दिन खाना हेल्दी है और लिवर के लिए फायदेमंद।

ग्रीक योगर्ट विद बेरीज

दही या फिर ग्रीक योगर्ट को बेरीज के साथ मिलाकर खाना प्रोटीन रिच होने के साथ ही गट हेल्थ के लिए अच्छा है। वहीं लिवर फैट लेवल को मैनेज करता है। ग्रीक योगर्ट में ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज को डालने से विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं जो लिवर सेल के स्ट्रेस को कम

Snacks That Can Reverse Fatty Liver

फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो हेल्दी बैलैंस मील और एक्सरसाइज के साथ हफ्ते में एक से दो बार इन स्नैक्स को इन चीजों के साथ पेयर करके खाना हेल्दी ऑप्शन है।

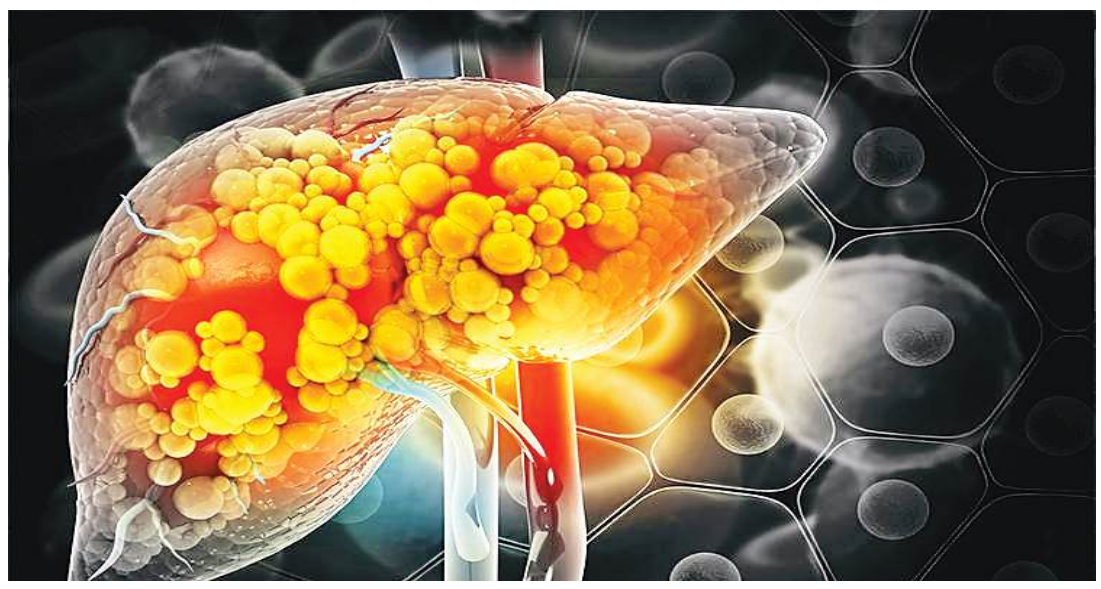

करने के साथ लिवर में हो रही इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। हफ्ते में एक या दो बार इसे खाना लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है।

डार्क चॉकलेट और नट्स

डार्क चॉकलेट को लिवर के लिए अच्छा नहीं माना जाता लेकिन डार्क चॉकलेट जिसमे कम से कम 70 परसेंट से ज्यादा कोकोआ हो उसमे पॉलीफेनॉल्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और ये स्ट्रेस लिवर को डैमेज करने का काम करता है। डार्क चॉकलेट में बादाम या पिस्ता को मिलाकर खाने से ये लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इन नट्स में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होता है। स्टडी के मुताबिक जो मरीज विटामिन ई रिच फूड्स और अनसैचुरेटेड फैट्स को डाइट में लेते हैं उनके फैटी लिवर में सुधार होता है। सप्ताह में एक से दो बार डार्क चॉकलेट और नट्स का काम्बिनेशन मिलाकर खाना हेल्दी है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

नारी शक्ति की डिजिटल उड़ान : तरक्की की नई परिभाषा

वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक बदलाव की शुरुआत हुई, तभी से भारत ने डिजिटल प्रगति की एक नई दिशा पकड़ी। इन 11 वर्षों में 'डिजिटल इंडिया मिशन' जैसे जन-केंद्रित अभियानों ने करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है- विशेषकर महिलाओं के लिए यह परिवर्तन आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और सम्मान की ओर एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। आज की 21वीं सदी में तकनीक सिर्फ शासन और अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को भी बदल रही है। और इस बदलाव की सबसे सशक्त मिसाल हैं वे महिलाएं, जो डिजिटल युग में नए अवसरों के साथ नई उड़ान भर रही हैं।

पहले डिजिटल साक्षरता बड़े शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन वहां भी इसकी पहुंच कम थी, और ग्रामीण महिलाओं के लिए तो तकनीक जैसे कहीं थी ही नहीं। लेकिन 'डिजिटल इंडिया' मिशन के तहत शुरू किए गए योजनाबद्ध प्रयासों ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है।

विशेष रूप से 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ने करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। अब वे स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेलीमेडिसिन और अन्य सुविधाओं का सीधे लाभ उठा रही हैं। इस अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 53% से ज़्यादा महिलाएं हैं। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन लेनदेन, उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ पा रही हैं।

2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो JAM ट्रिनिटी (जनधन, आधार, मोबाइल) के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन चुकी है, ने भारत में आर्थिक सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है। पहले जहाँ

जालंधर ब्रीज

सावित्री ठाकुर
(महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री भारत सरकार)

करोड़ों महिलाओं के पास बैंक खाते तक नहीं थे और सरकारी लाभ बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, वहीं अब जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन को एक नई दिशा दी है। इस डिजिटल क्रांति के कारण महिलाएं सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए अपने बैंक खातों में योजनाओं का लाभ पा रही हैं। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और पारिवारिक फैसलों में उनकी भूमिका भी मजबूत हुई है।

डिजिटल कौशल और भविष्य की तैयारी

तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। स्किल इंडिया मिशन और ई-स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से लाखों लड़कियों और महिलाओं को उनके मोबाइल पर अब प्रशिक्षण मिल रहा है। इससे वे बेहतर कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और नए रोजगार के अवसर प्राप्त कर पा रही हैं। यह बदलाव पहले के सीमित संसाधनों और पहुंच से कहीं अधिक व्यापक और सशक्त है।

SWAYAM और DIKSHA जैसे पोर्टल्स ने महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान जब समस्त दुनिया ठहर सी गई थी। अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के अंतर्गत 19 राज्यों के 27 जिलों में किशोरियों को डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकें।

डिजिटल युग में महिला उद्यमिता को नया संबल

एक समय था जब महिलाओं के छोटे व्यवसाय घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहते थे और बाज़ार तक पहुंच बनाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन बीते वर्षों में महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों की संख्या मंम जबरदस्त वृद्धि हुई है। महिला ई-हाट और GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) जैसे मंचों के माध्यम से अब महिलाएं न केवल अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल

चित्र विवरण : एआई द्वारा निर्मित चित्र

मार्केटिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने उन्हें एक उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने और अपना ब्रांड खड़ा करने का आत्मविश्वास दिया है।

स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा में तकनीक की भूमिका

POSHAN ट्रैकर, RCH पोर्टल और eSanjeevani जैसे डिजिटल टूल्स ने माताओं एवं एवं बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को बेहद आसान और प्रभावशाली बना दिया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहनें मोबाइल ऐप्स की मदद से लाभार्थियों की निगरानी, रिपोर्टिंग और सेवा वितरण का कार्य आसानी से कर पा रही हैं।

महिलाओं की सुरक्षा लंबे समय तक एक ऐसा क्षेत्र रहा, जहाँ तकनीक और त्वरित सहायता तंत्र की गंभीर कमी महसूस होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने ERSS-112, पैनिक बटन और महिला सुरक्षा ऐप्स जैसे प्रभावशाली उपाय लागू किए, जिनसे अब महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर खुद को पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित) में महिलाओं की भागीदारी

STEM जैसे क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी कभी सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। विज्ञान ज्योति और WISE-KIRAN योजना जैसी पहलें छात्राओं को STEM क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। भारतीय महिलाएं अब अंतरिक्ष अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल तकनीक महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व क्रांति लाई है। 2014 से अब तक समावेशी नीतियों, योजनाबद्ध प्रशिक्षण और तकनीक की पहुँच के ज़रिए लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर किया गया है। अमृत काल की ओर बढ़ते भारत में यह परिवर्तन महिलाओं को केवल भागीदार ही नहीं, बल्कि विकास यात्रा की अगुवा बना रहा है। एक डिजिटल रूप से सशक्त महिला आज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकसित भारत की निर्माता है।

माँ की शक्ति, बच्चों का भविष्य : योग से बदलता परिदृश्य

चाहे वह बोर्डरूम हो या युद्धभूमि – मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महिलाएँ ही बदलाव की वाहक होती हैं; महिलाओं के लिए अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, और योग इसकी कुंजी है।

योग की जन्मस्थली भारत में आज भी इस प्राचीन जीवनशैली को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के पोषण के लिए एक दार्शनिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। भगवद्गीता (अध्याय 2, श्लोक 50) में कहा गया है-"योग: कर्मसु कौशलम्", अर्थात् 'योग कर्मों में कौशल है।' भगवान श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि- सच्चा योग शारीरिक आसन या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात में परिलक्षित होता है कि हम अपने दैनिक कर्तव्यों को कितनी कुशलता और ध्यानपूर्वक निभाते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि योग में परिवर्तनकारी क्षमता है, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों के पोषण में, जो हमारे समाज की नींव हैं।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग ने वैश्विक मंच पर एक कल्याणकारी और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में पहचान प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जो भारत की महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक मान्यता सिद्ध करता है।

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम,"एक धरती, एक स्वास्थ्य के लिए योग" है । जो कि योग की सर्वसमावेशी और सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि "योग किसी कॉपीराइट, पेटेंट या रॉयल्टी से मुक्त है। यह लचीला है – आप इसे अकेले, समूह में, गुरु से या स्वयं भी सीख सकते हैं।" जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए।

जालंधर ब्रीज

अन्नपूर्णा देवी
(केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री)

भारत की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग दो-तिहाई है, और वे स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अतः उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, और योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

योग महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से अनेक लाभ प्रदान करता है। यह हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाता है, मानसिक तनाव को कम करता है, और मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार योग एक समग्र और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। योग को अपनाकर महिलाएँ गर्भावस्था से पूर्व और बाद के परिवर्तनशील समय की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनती हैं ।

प्रसव पूर्व योग, अपने विशेष आसनों और ध्यान तकनीकों के साथ, गर्भावस्था की परेशानियों को कम करता है, दर्द प्रबंधन में सहायता करता है, और ऊर्जा को बढ़ाता है। यह गर्भवती माताओं को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रसव के लिए तैयार करता है। प्रसवोत्तर योग, स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी रिकवरी, भावनात्मक सहायता, स्तनपान को बढ़ावा देने और माँ-बच्चे के रिश्ते को मजबूत करने में मदद करता है। महिलाओं में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, भारत में 25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक सशक्त नेटवर्क है, जो योग को महिलाओं और बच्चों के दैनिक जीवन में अपनाने के लिए जानकारी, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहा हैं।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की वकालत की है। वे कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का यह अनुमान है कि महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि से भारत के औद्योगिक उत्पादन में 9% तक की वृद्धि हो सकती है और 2047 तक हम एक उच्च आय वाले विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह सब तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारे पास शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिला कार्यबल हो।

आज की तेजी से बदलती दुनिया में, बच्चे भी जीवनशैली संबंधी विकारों, स्क्रीन पर निर्भरता और शैक्षणिक दबावों से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। योग इन चुनौतियों के लिए साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और सांस्कृतिक रूप से निहित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह एकाग्रता, याददाश्त बढ़ाने, भावनात्मक विनियमन, नींद की गुणवत्ता और तनाव के प्रबंधन को बेहतर करता है - जो समग्र बचपन के विकास के प्रमुख घटक हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से, हमारा मंत्रालय योग को बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास में शामिल कर रहा है, जो आजीवन स्वास्थ्यवर्धक आदतों की नींव रख रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। हमारी प्रमुख योजनाएँ, जैसे- आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और बाल देखभाल संस्थान आदि न केवल पोषण और कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि योग से जुड़ी विशेष गतिविधियों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इन केंद्रों में आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार विशेष योग मॉड्यूल्स लागू किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं।

आयकर विभाग चंडीगढ़ द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया

• **जालंधर ब्रीज** . चंडीगढ़

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, आयकर विभाग द्वारा आयकर भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ परिसर में योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर की मुख्य अतिथि श्रीमती वत्सला झा, प्रधान महा-निदेशक (जांच), उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, 1992 बैच की आईआरएस अधिकारी है। इस आयोजन का संचालन श्रीमती कोमल जोगपाल, आईआरएस, प्रधान मुख्य आयुक्त, पंचकूला एवं रिव्यू यूनिट-1, चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय थीम 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य हेतु योग' के अनुरूप आयोजित किया गया।

आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आयोजन में उल्लासपूर्वक और सामूहिक उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म के माध्यम से योग दिवस पर प्रकाश

डालते हुए की गई। इसके पश्चात प्राणायाम और ध्यान सत्र आयोजित किए गए, जिसका संचालन द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, चंडीगढ़ की योग प्रशिक्षक सुश्री मीना चौहान एवं सुव्रत ने किया।

योग सत्र में स्ट्रेचिंग व्यायाम और विभिन्न योगासन शामिल थे, जिसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम कराया गया। एक विशेष सत्र में 'हरि ओम्' ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन की सहायता से सात चक्रों का सशक्तिकरण किया गया, जिससे प्रतिभागियों को ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ।

अतुल्य भारत, अजेय भारत : मोदी युग ने पर्यटन को कैसे नया स्वरुप दिया

पिछले दशक में, भारत की पवित्र भूमि को सिर्फ़ देखा ही नहीं गया है - बल्कि इसे फिर से खोजा गया है। पहाड़ अब सिर्फ़ परिदृश्य नहीं रह गए हैं; वे जीवित अभयारण्य हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बर्फ से ढके मंदिरों से लेकर बोधगया की ध्यानपूर्ण शांति और सारनाथ की सुनहरी नीरवता तक, भारत की आध्यात्मिक आत्मा ने एक-एक तीर्थयात्री की भावना को उद्वेलित किया है। इस युग में पर्यटन, विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) के ज़रिए नहीं, बल्कि भक्ति, स्मृति और फिर से जुड़ने की सभ्यतागत प्रेरणा के ज़रिए तैयार किया गया था।

2014 और 2024 के बीच, इस आध्यात्मिक जागृति ने देश के सांस्कृतिक मानचित्र को नया स्वरुप दिया। केदारनाथ, जो कभी त्रासदी का प्रतीक था, फ़ीनिक्स की तरह उभरा - 2024 में यहां 16 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आये, जबकि एक दशक पहले यह संख्या केवल 40,000 थी। उज्जैन को महाकाल के शहर के रूप में पुनर्जीवित किया गया, इसने 2024 में 7.32 करोड़ आगंतुकों का स्वागत किया। प्रकाश और पवित्रता में पुनर्जन्म लेने वाली काशी ने 11 करोड़ लोगों को अपनी पवित्र गलियों में भ्रमण करते देखा। बोधगया और सारनाथ की गूंज कई महाद्वीपों में सुनायी दी, दोनों तीर्थस्थलों ने 2023 में 30 लाख से ज़्यादा साधकों को आकर्षित किया।

और फिर एक ऐसा क्षण आया, जो आंकड़ों से पार चला गया –जनवरी 2024 में अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। यह कोई उद्घाटन नहीं था; यह सभ्यता की धड़कन का जीर्णोद्धार था। महज छह महीनों में, 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हुआ –न सिर्फ देखने के लिए, बल्कि इससे जुड़ने के लिए। लगभग इतना ही ऐतिहासिक था, महाकुंभ 2025, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम था, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री आस्था और उत्कृष्टता के संगम पर पहुंचे। अयोध्या और प्रयागराज, साथ मिलकर, भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण के दो प्रकाश स्तंभ बन गए।

यह पर्यटन नहीं था—यह घर वापसी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वापसी को आकार, अवसंरचना और आत्मा दी गई। अब पर्यटन एक जांच सूची (चेकलिस्ट)-संचालित उद्योग नहीं रहा, बल्कि पवित्र 'स्व' को फिर से खोजने का एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी मंत्र - "भारत में विवाह करें, भारत की यात्रा करें, भारत में निवेश करें" - ने पर्यटन को एक सांस्कृतिक आह्वान में बदल दिया।

मोदी सरकार ने प्रारंभ से ही पर्यटन को राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ताकत के रूप में देखा है। स्वदेश दर्शन और इसके उन्नत रूप, स्वदेश दर्शन 2.0 के माध्यम से, पर्यटन मंत्रालय ने रामायण, बौद्ध, तटीय और आदिवासी जैसे विषयगत सर्किट के तहत 110 परियोजनाएँ विकसित कीं। 2014-15 में शुरू की गई मूल योजना में कुल 5,287.90 करोड़ रूपये की लागत से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 में, स्थाई गंतव्यों को विकसित करने के लिए 2,106.44 करोड़ रूपये के साथ 52 परियोजनाएँ जोड़ीं गईं।

चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) उप-योजना के तहत, 623.13 करोड़ रूपये की 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि एसएएससीआई योजना के अंतर्गत राज्य के नेतृत्व में पर्यटन अवसंरचना के विस्तार के लिए 3,295.76 करोड़ रूपये की 40 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी।

इसके साथ ही, प्रसाद योजना के जरिये उन्नत सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था और

जालंधर ब्रीज

गजेंद्र सिंह शेखावत
(केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, भारत सरकार)

स्वच्छता के साथ 100 तीर्थ शहरों को पुनर्जीवित किया गया। इन प्रयासों से भारत में 2023 में 250 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों की यात्रा दर्ज की गयी - जो अब तक का सबसे अधिक है।

2024-25 के केंद्रीय बजट में एक ऐतिहासिक घोषणा के तहत 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, उन्हें निवेश और वित्तपोषण को आसान बनाने के लिए अवसंरचना सामंजस्य मास्टर सूची (आईएचएमएल) में जोड़ा गया।

पुनरुद्धार केवल पवित्र स्थानों तक सीमित नहीं था। 2018 में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक बन गई, जिसे 2023 में 50 लाख से अधिक आगंतुक देखने आये। इसके चारों ओर इको-टूरिज्म पार्क, टेंट सिटी और आदिवासी संग्रहालय विकसित हुए हैं - जो सम्मान को अवसर में बदल रहे हैं।

भारत का सभ्यतागत आत्मविश्वास इसकी कूटनीति में परिलक्षित होने लगा। फ्रांस, जापान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के राजनेताओं का, न केवल दिल्ली में, बल्कि वाराणसी, उदयपुर, अयोध्या और महाबलीपुरम में भी स्वागत हुआ। सॉफ्ट पावर अब सॉफ्ट नहीं रही - यह 3डी अनुभव हो गयी। रिवर क्रूज़, दीपोत्सव, आध्यात्मिक भ्रमण और सांस्कृतिक प्रदर्शन ने राजकौशल को आत्मा के शिल्प में बदल दिया। इस बीच, अतुल्य भारत 2.0 ने देश को स्मारकों की भूमि से बदलकर बदलाव की भूमि बना दिया। ऋषिकेश में योग, केरल में आयुर्वेद, पूर्वोत्तर में जनजातीय त्योहार और कच्छ में शिल्प ने पर्यटन इकोसिस्टम को जीवंत व विशिष्ट स्थान प्रदान किया। विपणन को अब स्मृति से अलग करना मुश्किल था।

इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रभावशाली रही। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच, भारत ने पर्यटन में 18 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। प्रमुख आतिथ्य अवसंरचना परियोजनाओं में 2014-22 के दौरान 9 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ। केवल 2023 में, भारत ने 9.52 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ 2.31 लाख करोड़ रूपये (28.7 बिलियन डॉलर) की विदेशी मुद्रा अर्जित की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 47.9% की वृद्धि दर्ज की गयी। इस क्षेत्र ने 2023-24 में 84.63 मिलियन नौकरियों का सृजन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.46 मिलियन अधिक थीं - इस प्रकार पर्यटन क्षेत्र भारत के विकास और रोज़गार की आधारशिला के रूप में उभरा।

पर्यटन एक संपूर्ण आयाम वाले मिशन के रूप में विकसित हुआ। 'एक विरासत अपनाएँ' योजना के तहत प्रमुख स्थलों का कॉर्पोरेट प्रबंधन शुरू हुआ, जबकि उड़ान योजना ने शिरडी, जीरो और मिनिकॉय जैसे दूर-दराज के स्थानों को हवाई मार्ग से जोड़ा। राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन ने टिकट बुकिंग, डेटा और यात्रा कार्यक्रमों का एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में एकीकरण करना शुरू किया। पूर्वोत्तर- जो कभी उपेक्षित था- मुकुट के एक रत्न के रूप में उभरा। एक्ट ईस्ट नीति और अवसंरचना पर विशेष ध्यान की वजह से अरुणाचल, सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों में पर्यटकों का आगमन 2014 और 2022 के बीच दोगुना हो गया। जीवंत गांव कार्यक्रम ने किबिथु और माना जैसे दूरदराज के इलाकों को ऐसे गंतव्यों में बदल दिया, जहाँ देशभक्ति का मिलन प्रकृति और विरासत से होता है।

पर्यटन का विचार भी आकांक्षापूर्ण हो गया। "भारत में विवाह", राजस्थान और गोवा जैसे विवाह केंद्रों के लिए प्रोत्साहन, अभियान और अवसंरचना के समर्थन में तब्दील हो गया। इस बीच, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए 2022 में 6 लाख से अधिक विदेशी मरीज आये, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी उपचार स्थलों में से एक बन गया। 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता, सांस्कृतिक कूटनीति का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। दिल्ली तक सीमित रहने के बजाय, खजुराहो से कुमारकोम तक 60 से अधिक गंतव्यों में वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी हुई, जिनमें से प्रत्येक को स्थानीय कला, खान-पान और विरासत के साथ तैयार किया गया था। दुनिया भारत के साथ सिर्फ़ संवाद नहीं कर रही थी - बल्कि इसे अनुभव भी कर रही थी। लेकिन आंकड़ों के पीछे, असली परिवर्तन आध्यात्मिक था। भारत ने दुनिया से अपने स्मारकों को देखने के लिए अनुरोध करना बंद कर दिया। देश ने अपनी यादों को महसूस करने, अपनी शांति में स्वस्थ होने और अपनी विविधता का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित किया।

इस नए भारत में, पर्यटन मौसमी नहीं है - यह सभ्यतागत है। यह वह स्थल है, जहाँ दर्शन का विकास से, जहाँ तीर्थयात्रा का प्रगति से और जहाँ त्योहार का अवसंरचना से मिलन होता है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने दुनिया का सिर्फ़ स्वागत नहीं किया - बल्कि उसे गले लगाया।

जैसे भिक्षु बोधि वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, जैसे तीर्थयात्री केदारनाथ की ठंडी हवा में मंत्रोच्चार करते हैं, जैसे दुल्हनें महलनुमा गुंबदों के नीचे विवाह करती हैं और जैसे सीमावर्ती गाँव उत्सुक यात्रियों की मेजबानी करते हैं, एक सच्चाई हर पवित्र मार्ग और शांत गलियारे में गूंजती है: भारत केवल एक गंतव्य नहीं है, जहाँ की आप यात्रा करते हैं - यह एक ऐसा देश है, जहाँ आप कुछ शाश्वत की तलाश में बार-बार वापस आते हैं।

सीएम मान ने नीति आयोग की टीम के समक्ष राज्य की मांगें उठाईं

सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष रियायतें, सिंधु जल में हिस्सा मांगा और यमुना-सतलुज लिंक की मांग दोहराई

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नीति आयोग की टीम के सामने राज्य का पक्ष जोरदार ढंग से रखा और समर्थन की मांग की ताकि एक ओर पंजाब का समग्र विकास सुनिश्चित हो और दूसरी ओर इसके हितों की भी रक्षा हो। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद और प्रोग्राम डायरेक्टर संजीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम के साथ विचार-विमर्श के दौरान मुख्य मंत्री ने कहा कि यह उपयुक्त समय है जब आयोग को पानी और कृषि से संबंधित पंजाब की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए खुले दिल से मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और छह जिले अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का सीमा पर स्थित हैं। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष रियायतें देने से पंजाब के सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में फिर से जान फूंकने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पंजाब के सीमावर्ती जिलों को भी सहारा देने की जरूरत है। सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष रियायती पैकेज की मांग करते हुए, उन्होंने प्रत्येक सीमावर्ती जिले में एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की वकालत की, जिसमें विशेष ध्यान बासमती चावल उद्योग और लीची जैसे बागवानी उत्पादों पर दिया जाए। भगवंत सिंह ने सीमावर्ती जिलों में मौजूदा फोकल पॉइंट्स के नवीनीकरण और अमृतसर में प्रदर्शनी-कम-सम्मेलन केंद्र स्थापित करने की भी वकालत की।

मुख्यमंत्री ने एग्रो क्षेत्र के लिए पी.एल.आई. स्कीम, टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कर रियायतें, उद्योग के लिए परिवहन सब्सिडी, और सीमावर्ती जिलों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण और कार्यशील पूंजी की भी मांग की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तारों के बीच की जमीन के मालिकों के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि किसानों की 17,000 एकड़ से अधिक जमीन कांटेदार तारों के पार है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्तमान में किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह मुआवजा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से देने के बजाय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए, क्योंकि ये मेहनती किसान देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने के संबंध में, मुख्यमंत्री ने सभी 2107 सीमावर्ती गांवों के लिए बॉर्डर विंग होम गार्ड्स स्कीम को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक जवान के लिए 1999 में निर्धारित ड्यूटी भत्ता 45 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर न्यूनतम 655 रुपए करने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने बार-बार यमुना के पानी की वितरण के लिए बातचीत में शामिल होने की मांग की है क्योंकि यमुना-सतलुज-लिंक परियोजना के लिए 12 मार्च, 1954 को पुराने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें पुराने पंजाब को यमुना के पानी के दो-तिहाई हिस्से का हकदार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस समझौते में यमुना के पानी से सिंचाई के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया था। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन से पहले यमुना नदी रावी और ब्यास की तरह पुराने पंजाब से होकर बहती थी। भगवंत सिंह मान ने दुख व्यक्त किया कि पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल वितरण के समय यमुना के पानी पर विचार नहीं किया गया, जबकि रावी और ब्यास के पानी को ही विचार में लिया गया। उन्होंने कहा कि जब अब सिंधु नदी का पानी देश के आंतरिक राज्यों को दिया जाना है, तो पंजाब का इस पर प्राथमिक अधिकार है।

राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं पूरी पारदर्शिता, उचित ढंग से तथा निर्धारित समय सीमा में प्रदान करने के दिए निर्देश

'इजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम' शुरू करने के किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आम लोगों को राजस्व विभाग से संबंधित सेवाएं पूरी पारदर्शिता, सुचारू रूप से तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा अपने काम के लिए दफ्तर में आने वाले व्यक्तियों को हर संभव सुविधा प्रदान करें। बुधवार को स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में राजस्व विभाग की बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर में 'इजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम' को लागू करने की चल रही प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें 'मेरा घर मेरे नाम', खसरा मैपिंग, वसूली के मामले, म्यूटेशन, राजस्व कोर्स के मामले, ई-सेवा पेंडेंसी, जमाबंदी का डिजिटलीकरण आदि की प्रगति शामिल है।

डॉ. अग्रवाल ने 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के तहत गांवों में किए जा रहे ग्राउंड ट्रूथिंग (डोर-टू-डोर सर्वे) कार्य की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 890 गांवों में ड्रोन सर्वे के बाद 528 नक्शे-1 प्राप्त हुए, जिनके आधार पर गांवों में डोर-टू-डोर सर्वे का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 287 नक्शे-1 की ग्राउंड ट्रूथिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को डोर-टू-डोर सर्वे के काम में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिला राजस्व अधिकारी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर निगरानी रखें। जालंधर में 'इजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम' शुरू करने के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, स्टाफ के उचित प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण आदि पर जोर दिया। उन्होंने उप मंडल मैजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से तहसीलों का दौरा करने के लिए कहा ताकि बिना किसी बाधा के इस प्रणाली को निर्धारित दिन से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी। राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं के समय पर प्रावधान पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी देरी के म्यूटेशन, बंटवारा, जमाबंदी और निशानदेही के मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करें। उन्होंने कहा कि बंटवारे के जो मामले एक-दो साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कहा कि वे रिकवरी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लें और रिकवरी में तेजी लाएं।

जिला प्रशासन नशे के खात्मे के लिए कर रहा है सुहृद प्रयास : डिप्टी कमिश्नर

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जिला प्रशासकीय परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तर पर अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस का नेतृत्व किया। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर जिले के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन जालंधर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों के सहयोग से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा नशे के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम 'युद्ध नशे के विरुद्ध ' के तहत सिविल व पुलिस प्रशासन नशे के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे पर निर्भर लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

भगवंत मान सरकार और अनन्या बिरला फाउंडेशन ने नशे के खिलाफ जंग में तेजी लाने के लिए मिलाया हाथ

डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए समझौता

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नशाखोरी और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता पंजाब सरकार और डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली तथा विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अमृतसर के बीच अनन्या बिरला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चल रही जंग का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने की यह अनूठी पहल राज्य में नशे के खतरे से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मिड-डे मील स्टाफ को मिलेगा 16 लाख का बीमा कवर

शिक्षा मंत्री ने कहा- स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,000 से अधिक कुक-कम-हेल्परों के लिए किया समझौता

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने केनरा बैंक के साथ साझेदारी में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 44,301 मिड-डे मील कुक-कम-हेल्परों को 16 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू की है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस और स्कूल शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा, आईएएस की उपस्थिति में डायरेक्टोरेट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (मिड-डे मील) और केनरा बैंक, चंडीगढ़ के बीच एक समझौता (एमओयू) साइन किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य कुक-कम-हेल्परों को वित्तीय सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।

345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वे पार्टियां हैं जो वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों के दौरान किसी भी चुनाव में भाग लेने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में असफल रही हैं और जिनके दफ्तरों का भौतिक रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सका है। ये 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।

आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड 2800 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में से कई पार्टियां आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रही हैं। इसी कारण भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ऐसी पार्टियों की पहचान के लिए एक देशव्यापी अभ्यास चलाया गया, जिसके अंतर्गत अब तक 345 ऐसी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पहचान की जा चुकी है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को बिना कारण सूची से न हटाया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इन पार्टियों को संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।किसी भी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को सूची से हटाने का अंतिम निर्णय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। देश में राजनीतिक पार्टियां (राष्ट्रीय/राज्य/रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं। इस प्रावधान के अनुसार, एक बार कोई संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो उसे कर में छूट सहित कुछ विशेष अधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान के सार्थक परिणाम आने शुरू : डिप्टी कमिश्नर

कपूरथला में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नशा रोकथाम दिवस

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा नशे के खात्मे के लिए शुरू किया गया "युद्ध नशे विरुद्ध" अभियान के सार्थक परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। पंचाल यहां सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा अंतरराष्ट्रीय नशा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान संबोधित कर रहे थे।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशे के कोढ़ को समाप्त करने के लिए "युद्ध नशे विरुद्ध" अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए वॉकथॉन, साइकिलथॉन भी करवाई गई हैं। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों में नशा विरोधी सेमिनार, रैलियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोग पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान का हिस्सा बनें।

पंचाल ने लोगों से अपील की कि वे नशा विरोधी लड़ाई में पंजाब सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में 25 और बेडों की व्यवस्था की जा रही है। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बलविंदर जीत सिंह ने बताया कि हर साल 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मीत हेयर ने उप-राष्ट्रपति को लिखा पत्र

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पंजाब विश्वविद्यालय में रोष प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और देश के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर यह फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की है।

लोकसभा सदस्य ने पत्र में लिखा है कि पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों से धरना न देने और विरोध प्रदर्शन न करने का लिखित शपथ-पत्र लेना, उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह फैसला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय जहां छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, वहीं यह एक तानाशाही सोच का भी प्रतीक है।

आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस की तानाशाही पर भाजपा का प्रहार

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हुए 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया, जिसमें आपातकाल के काले अध्याय को याद किया गया। बीजेपी लीगल सेल पंजाब के संयोजक एडवोकेट एन.के. वर्मा ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस सरकार ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को कुचलते हुए आपातकाल घोषित किया था। उन्होंने कहा कि "इंदिरा गांधी की सत्ता की भूख ने पूरे देश को जेलखाना बना दिया था।

प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले जड़ दिए गए थे, कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। प्रेस, न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। हजारों राजनैतिक विरोधियों, छात्रों, पत्रकारों और साधारण नागरिकों को जेल में बंद कर दिया गया।" एन.के. वर्मा ने कहा कि "विडंबना यह है कि वही कांग्रेस आज संविधान की दुहाई देकर 'संविधान खतरे में है' का झूठा शोर मचाती है, जबकि इतिहास गवाह है कि असल में उसी ने संविधान को सबसे अधिक कुचला है।"

उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। केवल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वर्मा ने कहा कि "जो दल वर्षों तक सत्ता में रहकर संविधान का अपमान करता रहा, वही आज खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने का ढोंग कर रहा है।"

आईसीसी ने जारी की टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग दो शतक जड़ने के बाद पंत को हुआ फायदा

स्पोर्ट्स डेस्क. आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में दो शतक जड़ने के बाद फायदा हुआ है। वह एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें पर पहुंच गए हैं। पंत के खाते में फिलहाल 801 रेटिंग अंक हैं। ये उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है। वह टेस्ट में 800 रेटिंग तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर हैं। उन्होंने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे। वह जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी मारने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं। वह ये कमाल करने वाले कुल सातवें भारतीय हैं।

फोटो-बीसीसीआई

भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने बल्लेबाजों की सूची में एक जैसी छलांग लगाई है। दोनों को पांच-पांच स्थानों का लाभ मिला है। जहां गिल 20वें जबकि डकेट आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं। गिल (147) नेलीड्स की पहली पारी में शतक जमाया था। डकेट ने पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में सेंचुरी ठोकी। उनकी 149 रनों की पारी के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने 371 का टारगेट आसानी से चेज कर लिया था। डकेट को प्लेयरऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।

टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में केवल दो भारतीय हैं। यशस्वी जायसवाल (101) शतक मारने के बावजूद चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़े। इंग्लैंड के ओली पोप और जेमी स्मिथ ने रैंकिंग में सुधार किया है। इंग्लैंड के जो रूट नंबर वन बल्लेबाज हैं। उनके 889 अंक हैं। रूट ने पहले टेस्ट में नाबाद अर्धशतक जड़ने के अलावा 28 रनों की पारी खेली। उनके हमवतन हैरी ब्रूक (874) दूसरे नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन (867) तीसरे स्थान पर हैं।

वहीं टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर कायम हैं। उनके खाते में 907 रेटिंग अंक हैं। बुमराह ने लीड्स की पहली पारी मं पांच विकेट चटकाए थे। हालांकि, उन्हें दूसरी पारी में कोई सफलता नहीं मिली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को टेस्ट ऑलराउंडर्स की सूची में तीन स्थान के फायदा मिला है। वह अब पांचवें पायदान पर आ गए हैं। स्टोक्स ने मैच में कुल पांच विकेट लेने के अलावा 20 और 33 रनों की पारी खेली।

सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : चंदन ग्रेवाल

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

पंजाब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की रीढ़ हैं और प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें सम्मानजनक जीवन और कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। वे आज जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स, होशियारपुर में नगर निगम अधिकारियों और सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर डा. अमनदीप कौर सहित अन्य नगर निगम व नगर कौंसिलों के अधिकारी एवं यूनियन पदाधिकारी भी उपस्थित थे। चेयरमैन श्री ग्रेवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों को सीधे तौर पर सुनना, उनका समाधान करना और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करना है।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री ग्रेवाल ने बताया कि कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। वहीं, कुछ मांगें ऐसी हैं जो राज्य स्तर की हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पंजाब के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उन्हें भी शीघ्रता से निपटाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन, सुरक्षा उपकरण और आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई कर्मचारी खुद को उपेक्षित न महसूस करे।

चंदन ग्रेवाल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके योगदान को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आयोग इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.